शीर्ष प्राथमिकता समयबद्ध

संख्या- 6/2021/बी-2-44/दस-2021-आर-2/2016टी.सी.

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 04 फरवरी, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2020-2021 के तृतीय त्रैमास (माह अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक) के प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-टी.एम.-2/ग्रुप-4/लेखा मिलान/76342, दिनांक 18.01.2021 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आंकड़ों के त्रैमासिक लेखा मिलान की प्रक्रिया के क्रम में माह अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक के लेखांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिये दिनांक 11 फरवरी, 2021 से 18 मार्च, 2021 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वित्तीय वर्ष 2020-2021 के तृतीय त्रैमास (माह अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा मिलान कार्य कराये जाने हेतु संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डी.डी.ओ. रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.-4 एवं बी.एम.-13), महालेखाकार कार्यालय के ई-मेल- agaeuttarpradesh1@cag.gov.in एवं फैक्स नं0-0532-2420880 (राजकोष प्रकोष्ठ) या 0532-2421987 पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करायें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-81 एवं 83 में अपने विभाग की योजनाओं से सम्बन्धित लेखाशीर्षों के व्यय के आंकड़ों का मिलान कार्य भी नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के साथ ही सुनिश्चित कराया जायेगा। नियंत्रक अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़ें अन्तिम समझे जायेंगें।

4- लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है अथवा वे विभाग जो निर्धारित तिथि पर लेखामिलान न करा पाये हो, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखामिलान कार्य दिनांक 11.02.2021 एवं 18.02.2021 को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-6/2021/बी-2-44(1)/दस-2021-आर-2/2016टी.सी., तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र पत्र संख्या-टी.एम.-2/ग्रुप-4/लेखामिलान/76342, दिनांक **18.01.2021** के संदर्भ में।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार, (लेखा व हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

...../3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-6/2021/बी-2-44/दस-2021-आर-2/2016टी.सी. दिनांक 04.02.2021

वित्तीय वर्ष 2020-2021 से सम्बन्धित माह अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
1	आबकारी	11.02.2021
2	आवास	
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/खादी एवं ग्रामोद्योग/हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उद्योग/मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	
4	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	
5	ऊर्जा	12.02.2021
6	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	
7	रेशम विभाग	
8	कृषि विभाग	
9	परती भूमि विकास	15.02.2021
10	समन्वय विभाग	
11	कृषि विपणन विभाग	
12	भूमि विकास एवं जल संसाधन	
13	ग्राम्य विकास विभाग	16.02.2021
14	भूगर्भ जल विभाग	
15	लघु सिंचाई	
16	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
17	पंचायती राज विभाग	17.02.2021
18	पशुधन	
19	दुग्ध विकास	
20	मत्स्य	
21	सहकारिता	18.02.2021
22	कार्मिक एवं नियुक्ति	
23	खाद्य एवं रसद	
24	खेल एवं युवा कल्याण	
25	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	19.02.2021
26	गृह (कारागार)	
27	गृह (पुलिस)	
28	नागरिक सुरक्षा	
29	राजनीतिक पेंशन	22.02.2021
30	गृह (गोपन)	
31	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
32	परिवार कल्याण विभाग	
33	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी)	23.03.2021
34	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
35	होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	
36	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	
37	नगर विकास	24.02.2021
38	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	
39	नागरिक उड्डयन	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

40	भाषा	25.02.2021
41	नियोजन	
42	निर्वाचन	
43	न्याय	01.03.2021
44	परिवहन	
45	पर्यावरण	
46	पर्यटन विभाग	
47	प्रशासनिक सुधार	02.03.2021
48	प्राविधिक शिक्षा	
49	अल्पसंख्यक कल्याण	
50	महिला एवं बाल विकास	03.03.2021
51	राजस्व	
52	सहायता एवं पुनर्वास	
53	राष्ट्रीय एकीकरण	04.03.2021
54	लोक निर्माण	
55	राज्य सम्पत्ति विभाग	
56	वन	
57	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा)	05.03.2021
58	विधान परिषद सचिवालय	
59	विधान सभा सचिवालय	
60	विधायी एवं संसदीय कार्य	
61	वित्त विभाग	08.03.2021
62	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	
63	बेसिक शिक्षा	
64	माध्यमिक शिक्षा	
65	उच्च शिक्षा	09.03.2021
66	श्रम	
67	सचिवालय प्रशासन	
68	कार्यक्रम कार्यान्वयन	
69	विकलांग कल्याण	10.03.2021
70	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
71	समाज कल्याण	
72	जनजाति कल्याण	
73	सतर्कता विभाग	12.03.2021
74	सामान्य प्रशासन	
75	मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल)	
76	सार्वजनिक उद्यम	
77	सूचना	15.03.2021
78	संस्थागत वित्त	
79	स्टाम्प एवं पंजीयन	
80	मनोरंजन कर	
81	सैनिक कल्याण	16.03.2021
82	व्यापार कर	
83	सांस्कृतिक कार्य	
84	सिंचाई एवं जल संसाधन	
85	उक्त सूची के अतिरिक्त कोई विभाग शेष हो अथवा वे विभाग जो निर्धारित तिथि पर लेखामिलान न करा पाये हो	17.03.2021 व 18.03.2021

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।